3 कमलनाथ ही कर सकते हैं कांग्रेस को ताकतवर

5 भरोसेमंद और निष्ठावान राजनेता तोमर

7 धराली त्रासदी प्राकृतिक आपदा नहीं चेतावनी है

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 16 अंक : 14 प्रति सोमवार, 11 अगस्त 2025 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

भाजपा विधायक संजय पाठक पर मोहन सरकार ने कसा शिकंजा

खनन घोटाले में सरकार वसूलेगी 443 करोड़, कई स्तर पर जांच जारी

कवर स्टोरी

-विजया पाठक
एडिटर

कभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाने वाले भाजपा नेता और विजयराघवगढ़ के विधायक संजय पाठक की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सत्ता संभालते ही स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार नियमों को तोड़ने और संसाधनों का दुरुपयोग करने वाले नेताओं व अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, चाहे वह किसी भी दल या पद के हों। अब इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मध्यप्रदेश के बड़े खनन माफियाओं में शामिल संजय पाठक से जुड़ी तीन कंपनियों पर 443 करोड़ रुपये की वसूली की तैयारी कर ली है।

तीन कंपनियों पर गंभीर आरोप

जबलपुर जिले के सिहोरा क्षेत्र में संचालित आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट- ये तीनों कंपनियां संजय पाठक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी बताई जाती हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने निर्धारित परमिशन से कई गुना अधिक खनन किया। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक, इन कंपनियों ने खनन की अनुमति सीमा का उल्लंघन करते हुए सैकड़ों करोड़ रुपये के खनिज का अवैध उत्खनन किया। खनिज विभाग की रिपोर्ट और स्वतंत्र ऑडिट में यह भी सामने आया कि खनन के दौरान न तो पर्यावरणीय मानकों का पालन किया गया और न ही निर्धारित रॉयल्टी समय पर जमा की गई। इससे सरकार को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। इसी आधार पर 443 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस तैयार किया गया है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित भारत निर्माण के लिए राज्य का संकल्प 'अंजोर विजन@2047', प्रधानमंत्री को किया रजत जयंती समारोह के लिए आमंत्रित

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है, जिसे 'अंजोर विजन@2047' नाम दिया गया है। यह विजन दस्तावेज विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तैयार किया गया है और इसमें राज्य के समावेशी एवं सतत विकास की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस योजना का उद्देश्य अगले दो दशकों में छत्तीसगढ़ को शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शामिल करना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के रजत जयंती वर्ष के मुख्य समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ इस वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे कर रहा है और यह समारोह ऐतिहासिक रूप से राज्य के विकास यात्रा के मील के पत्थरों को रेखांकित करेगा।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तैयार संकल्प पत्र ऐतिहासिक रूप से राज्य के विकास यात्रा के मील के पत्थरों को रेखांकित करेगा

अंजोर विजन@2047–विकास का समग्र खाका

अंजोर विजन@2047 को तैयार करते समय सरकार ने न केवल वर्तमान चुनौतियों और अवसरों का आकलन किया, बल्कि वैश्विक बदलावों और तकनीकी प्रगति को भी ध्यान में रखा है। इस दस्तावेज का नाम 'अंजोर' छत्तीसगढ़ की स्थानीय बोली में 'रोशनी' या 'प्रकाश' का प्रतीक है, जो राज्य के उज्ज्वल भविष्य का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब प्रत्येक राज्य अपने संसाधनों और क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करते हुए समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़े। इसी सोच के तहत यह विजन पांच मुख्य स्तंभों पर आधारित है

1. शिक्षा एवं कौशल विकास
2. स्वास्थ्य एवं पोषण
3. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
4. उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी ढांचा
5. पर्यावरण एवं सतत विकास

(शेष पेज 8 पर)

खनन घोटाले में सरकार वसूलेगी 443 करोड़, कई स्तर पर जांच जारी

(पेज 1 का शेष)

ईओडब्ल्यू में दर्ज शिकायत और जांच

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में इस मामले की शिकायत आशुतोष मिश्रा ने दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि इन कंपनियों ने मिलीभगत से खनन परमिट की शर्तों को तोड़ा, सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया और राजस्व का बड़ा हिस्सा छुपाया। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की, जिसमें कई दस्तावेज और गवाहों के बयान सामने आए हैं। जांच में यह भी पता चला कि इन कंपनियों को विभिन्न समय पर सरकारी अफसरों ने बिना उचित कारण के अतिरिक्त खनन की अनुमति दी, जिससे यह संदेह और गहरा हो गया कि पूरे प्रकरण में राजनीतिक दबाव और भ्रष्टाचार की भूमिका रही है।

मंत्री रहते हुए दिया कई घोटालो को अंजाम

संजय पाठक, जिनका नाम पहले भी खनन विवादों में आ चुका है, पर आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर अरबों रुपये का घोटाला किया। आरोप है कि उन्होंने मंत्रालय में रहते हुए संबंधित विभागों में अपने लोगों की नियुक्ति कराई, ताकि खनन और परिवहन से जुड़े सभी नियम उनके पक्ष में बदले जा सकें। सूत्र बताते हैं कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने न केवल अवैध खनन को बढ़ावा दिया बल्कि अवैध रूप से निकाले गए खनिज को विभिन्न निजी चैनलों के माध्यम से बाहर भी

भेजा। इन सभी गतिविधियों के चलते प्रदेश को बड़े राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा।

विधानसभा में गरमाया मामला

विधानसभा के चालू सत्र में विपक्ष ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। विपक्षी दलों के विधायकों ने सवाल किया कि आखिर सरकार इस बड़े घोटाले में शामिल नेताओं पर कार्रवाई कब करेगी। इस पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट जवाब दिया कि "किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह सत्ता पक्ष का विधायक ही क्यों न हो।" उन्होंने बताया कि जांच कई स्तरों पर चल रही है और दोषी पाए जाने पर सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी के मामलों में सख्त कार्रवाई होगी, भले ही आरोपित भाजपा से ही क्यों न हो।

क्या होंगे जेल जाने वाले पहले भाजपा विधायक?

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यदि जांच में आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो संजय पाठक मोहन सरकार के कार्यकाल में जेल जाने वाले पहले भाजपा विधायक बन सकते हैं। यह स्थिति भाजपा के लिए भी असहज होगी, क्योंकि पाठक कभी पार्टी के प्रमुख चेहरे और शिवराज सिंह चौहान के करीबी सहयोगियों में गिने जाते थे।

मोहन सरकार की सख्त छवि

मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद संभालते ही खनन, भू-माफिया और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने का ऐलान किया था। पिछले कुछ महीनों में खनन क्षेत्र में कई बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध खदानों को सील करना, मशीनरी जब्त करना और भारी जुर्माने लगाना शामिल है। सरकार का दावा है कि इन कार्रवाइयों से न केवल राजस्व में बढ़ोतरी होगी बल्कि खनिज संपदा के संरक्षण में भी मदद मिलेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कार्रवाई चुनिंदा लोगों तक सीमित है और कई बड़े नाम अब भी जांच के दायरे से बाहर हैं।

इस पूरे मामले में राजनीतिक असर

संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई का असर न केवल उनके व्यक्तिगत राजनीतिक भविष्य पर पड़ेगा बल्कि प्रदेश की सत्ता समीकरणों पर भी। विजयराघवगढ़ में पाठक की मजबूत पकड़ रही है और यदि वे कानूनी मुश्किलों में घिरते हैं तो भाजपा को वहां राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला मोहन यादव सरकार के लिए एक 'लिटमस टेस्ट' है- क्या वे वास्तव में निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे या फिर मामला समय के साथ ठंडा पड़ जाएगा।

राजनीतिक करियर और विवादों का रिश्ता

संजय पाठक का राजनीतिक सफर विवादों से अछूता नहीं रहा है। वे कभी कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में भाजपा में शामिल होकर शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी नेताओं में गिने जाने लगे। मंत्री पद पर रहते हुए भी उनके खिलाफ खनन से जुड़े अनियमितताओं के आरोप लगते रहे, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की गति धीमी रही। सत्ता परिवर्तन के बाद अब उनके खिलाफ एक के बाद एक पुराने मामले खुलने लगे हैं।

मोहन सरकार की सख्ती

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए साफ कहा कि सरकार किसी भी नेता या अफसर को नियम तोड़ने की अनुमति नहीं देगी, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। उन्होंने कहा कि खनन माफियाओं पर कार्रवाई में किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव आड़े नहीं आएगा और अवैध कमाई को सरकारी खजाने में वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा।

खनन घोटाले की गहराई को समझना जरूरी

खनन विभाग की प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक, आनंद माइनिंग, निर्मला मिनरल्स और पैसिफिक एक्सपोर्ट ने खदानों से उतनी मात्रा में खनिज निकाले, जितनी की अनुमति नहीं थी। कई बार तो खनन परमिट में दर्ज सीमा से तीन गुना ज्यादा खनन किया गया। इसके अलावा, खनिजों के परिवहन और बिक्री के दौरान भी रॉयल्टी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई। इन कंपनियों के खातों की जांच में कई संदिग्ध लेन-देन भी सामने आए हैं।

कुल मिलाकर विधायक पाठक पर कार्रवाई केवल एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं, बल्कि यह संकेत है कि मोहन सरकार अवैध खनन और भ्रष्टाचार के मामलों में कितनी गंभीर है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह कार्रवाई कितनी दूर तक जाती है और क्या सच में संजय पाठक प्रदेश के पहले सत्तारूढ़ भाजपा विधायक होंगे जो खनन घोटाले में जेल की हवा खाएंगे। लेकिन इतना तय है कि इस समय उनकी राजनीतिक जिंदगी के सबसे कठिन दिन शुरू हो चुके हैं।

अशोक वानखेड़े ने वंचित वर्गों की आवाज़ को किया बुलंद

कलम के सिपाही

अशोक वानखेड़े भारतीय पत्रकारिता जगत की एक प्रमुख और जानी-मानी हस्ती हैं। उन्होंने अपनी पत्रकारिता से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, बल्कि सामाजिक मुद्दों, खासकर दलित, आदिवासी और वंचित वर्गों की आवाज़ को बुलंद करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दिल्ली में सक्रिय रहने वाले अशोक वानखेड़े लंबे समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें बेबाक, निष्पक्ष और जनपक्षधर पत्रकारिता के लिए जाना जाता है। अशोक वानखेड़े का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद शिक्षा को अपना हथियार बनाया। सामाजिक न्याय और समता के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने पत्रकारिता को अपना माध्यम बनाया, ताकि वे समाज के हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ बन सकें। उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत एक स्थानीय अखबार से की थी और धीरे-धीरे अपने कौशल, मेहनत और सामाजिक समझ के चलते राष्ट्रीय मीडिया में अपनी मजबूत जगह बनाई। वे कई प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टीवी चैनलों से जुड़े रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक टीवी पत्रकारिता में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अनेक राष्ट्रीय बहसों में अपनी बेबाक राय और तथ्यों के साथ उपस्थिति दर्ज कराई।

अशोक वानखेड़े की पहचान एक ऐसे पत्रकार के रूप में है, जो सत्ता से सवाल पूछने का साहस रखता है और सच को बिना डर के सामने लाता है। वे सामाजिक मुद्दों, खासकर आरक्षण, दलित अत्याचार, सामाजिक असमानता और शिक्षा जैसे विषयों पर खुलकर बोलते हैं। उनकी लेखनी और वक्तव्यों में सामाजिक सरोकार स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। उनकी पत्रकारिता में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का गहरा प्रभाव है। वे अक्सर अपने लेखों और भाषणों में अंबेडकरवाद की चर्चा करते हैं और समाज में समता, न्याय और बंधुता के सिद्धांतों को स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं।

अशोक वानखेड़े ने विभिन्न मंचों पर व्याख्यान दिए हैं और कई सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर जनजागृति का कार्य भी किया है। उन्होंने पत्रकारिता को केवल पेशा न मानकर सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना है। आज भी वे देशभर में हो रहे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं और सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं। उनकी पत्रकारिता नए पत्रकारों के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि ईमानदारी, निडरता और जनभावनाओं की समझ रखने वाला पत्रकार समाज में सार्थक बदलाव ला सकता है। अशोक वानखेड़े न केवल एक पत्रकार हैं, बल्कि वे एक विचारक, वक्ता और सामाजिक योद्धा भी हैं, जिन्होंने पत्रकारिता को जनसेवा का माध्यम बनाया है।

पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ की सक्रियता से मिलेगी कांग्रेस के पुनर्गठन की नई रणनीति

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखी जा रही है और इसके केंद्र में हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा और हर्रई इलाकों में भाजपा के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाकर कमलनाथ ने न केवल अपनी राजनीतिक सक्रियता का संकेत दिया है, बल्कि प्रदेश की राजनीति में एक नई रणनीतिक परत भी जोड़ दी है। यह घटनाक्रम सिर्फ दल-बदल की राजनीति नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक, संगठनात्मक और रणनीतिक निहितार्थ हैं।

कमलनाथ की वापसी शैली मौन नहीं, मैदान में

पिछले कुछ महीनों से यह चर्चा जोरों पर थी कि क्या कमलनाथ सक्रिय राजनीति से किनारा कर रहे हैं या पार्टी में सीमित भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन इस सदस्यता अभियान ने इन तमाम अटकलों को विराम दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया है कि वे पार्टी को केवल नेतृत्व ही नहीं देंगे, बल्कि मैदान में उतरकर कांग्रेस को जमीनी ताकत भी दिलवाएंगे। उनका यह अभियान केवल स्थानीय स्तर की रणनीति नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस के लिए संदेश का कार्य करेगा।

भाजपा से मोहभंग और कांग्रेस की स्वीकार्यता

छिंदवाड़ा के गौंडवाना और आसपास के क्षेत्र भाजपा के परंपरागत गढ़ माने जाते रहे हैं। ऐसे में भाजपा के 500 से अधिक कार्यकर्ताओं का कांग्रेस में शामिल होना केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि भाजपा के आंतरिक संकट की ओर संकेत करता है। कमलनाथ ने यह स्पष्ट किया कि ये कार्यकर्ता भाजपा द्वारा उपेक्षित महसूस कर रहे थे और वे किसी षड्यंत्र या टूट-फूट की राजनीति के तहत नहीं, बल्कि सम्मान और पहचान की तलाश में कांग्रेस में आए हैं। यह कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जो दिखाता है कि पार्टी अब केवल नीतियों या विचारों तक सीमित नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और सामाजिक जुड़ाव की राजनीति भी कर रही है।

भाजपा में लगातार उपेक्षित हो रहे 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ पर जताया भरोसा, संगठनात्मक संस्कृति और समावेशी दृष्टिकोण को लेकर आगे बढ़ रहे कमलनाथ

कमलनाथ ने ही प्रदेश में मेट्रो की नींव रखवाई थी

मध्यप्रदेश में मेट्रो की सबसे पहले कमलनाथ ने ही नींव रखवाई थी। यह बात उस समय की है जब प्रदेश में बाबूलाल गौर नगरीय विकास मंत्री थी और केन्द्र में कमलनाथ मंत्री थे। कमलनाथ ने बाबूलाल को दिल्ली बुलाकर कहा कि मैं सब जगह जाता हूं और सब जगहों पर मेट्रो का शिलान्यास हो रहा है लेकिन मध्यप्रदेश में नहीं। तब बाबूलाल ने कहा था कि हमारे पास तो डीपीआर के भी पैसे नहीं हैं। उसी समय कमलनाथ ने कहां कि आप डीपीआर बनवाईये, पैसे मैं देता हूं। उस समय कमलनाथ ने डीपीआर के 15 करोड़ रुपये दिये थे। इस बात का जिक्र हाल ही में कमलनाथ ने विधानसभा में किया था। कहने का मतलब है कि कमलनाथ को प्रदेश के विकास की चिंता हमेशा रही है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो कमलनाथ ने हमेशा प्रदेश के विकास पर फोकस किया।

समाज को जोड़ने की कांग्रेस की परंपरा

कांग्रेस कार्यकर्ताओं और हाल में शामिल हुए भाजपा से आए सदस्यों का मानना है कि कांग्रेस 'समाज को तोड़ने' की नहीं, बल्कि 'समाज को जोड़ने' की राजनीति करती है। यही वह भावनात्मक जुड़ाव है, जो वर्तमान समय में भारतीय राजनीति में दुर्लभ होता जा रहा है। इस बात को राजनीतिक विश्लेषकों ने भी रेखांकित किया है कि कांग्रेस की जमीनी पकड़ भले ही कमजोर हुई हो, लेकिन उसकी संगठनात्मक संस्कृति और समावेशी दृष्टिकोण अभी भी लोगों को आकर्षित करने में सक्षम है।

कमलनाथ की विकास नीति की मिसाल

कमलनाथ के राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन केवल संगठन या सदस्यता अभियानों से नहीं किया जा सकता। उनका प्रशासनिक अनुभव और विकासशील सोच भी उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा है। बतौर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने मध्यप्रदेश में मेट्रो परियोजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू की। बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वयं इसकी नींव रखी। यह एक दुर्लभ संयोग है कि एक नेता ने किसी परियोजना की परिकल्पना भी की और उसकी आधारशिला भी स्वयं रखी। इससे यह प्रमाणित होता है कि कमलनाथ की दृष्टि सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि विकासोन्मुखी भी रही है।

विधानसभा में स्पष्ट और आक्रामक विपक्ष की भूमिका

विधानसभा में कमलनाथ ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि "मध्यप्रदेश में घोषणाओं और आश्वासन की सरकार चल रही है।" यह वक्तव्य केवल आलोचना नहीं, बल्कि जनता को यह बताने का प्रयास भी है कि प्रदेश में कथित विकास की कहानी केवल कागजों और नारों तक सीमित है। उनका यह बयान चुनावी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक सक्रिय, स्पष्ट और तथ्यात्मक विपक्ष जनता को यह भरोसा दिला सकता है कि सत्ता के विकल्प के रूप में कांग्रेस न केवल तैयार है, बल्कि सक्षम भी है।

प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय कांग्रेस के बीच तालमेल

पार्टी में निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता और संवाद से ही कांग्रेस भविष्य में मजबूत विकल्प बन सकती है। कमलनाथ द्वारा शुरू की गई यह पहल केवल एक राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की रणनीति का हिस्सा है। छिंदवाड़ा से शुरू हुआ यह सदस्यता अभियान यदि प्रदेश भर में फैला तो कांग्रेस को नई ऊर्जा और दिशा मिल सकती है। भाजपा के भीतर असंतोष, जनता में विकास के ठोस परिणामों की मांग और कांग्रेस के समावेशी दृष्टिकोण के बीच कमलनाथ एक सेतु की तरह कार्य कर रहे हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव, राजनीतिक सूझबूझ और जमीनी पकड़ कांग्रेस को आगामी चुनावों में मुकाबले में बनाए रखने की क्षमता रखती है। यदि कांग्रेस इस पहल को संगठनात्मक रूप से मजबूत करती है और वैकल्पिक नीतियों को जनसामान्य तक पहुंचाने में सफल होती है तो यह कहा जा सकता है कि कमलनाथ की यह वापसी सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि कांग्रेस के लिए नवजीवन का आरंभ हो सकती है।

सत्ता, सट्टा, ड्रग्स और सवाल नरेला विधानसभा से जुड़े विवाद पर राजनीतिक हलचल

राजधानी में आखिर किसके राजनीतिक संरक्षण से ड्रग्स का कारोबार कर रहा था यासीन मछली, यासीन पर हुई कार्यवाही पर सारंग की चुप्पी ने उठाए कई सवाल

-विजया पाठक

मध्यप्रदेश की राजनीति में इन दिनों नरेला विधानसभा क्षेत्र चर्चा में है। सूत्रों के अनुसार, यहां लंबे समय से चल रहे एमडी ड्रग्स का कारोबार कर रहे भाजपा नेता यासीन मछली और पुलिस के चंगुल में गिरफ्तार यासीन मछली को लेकर राजनीतिक संरक्षण को लेकर प्रदेश की सियासत गरमा रही है। भाजपा के नेता और वर्तमान में खेल एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल आने वाले दिनों में सारंग को

इस मामले पर स्पष्टीकरण के लिए तलब कर सकते हैं।

यासीन मछली और कोकता फार्म हाउस

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, नरेला क्षेत्र के कथित सट्टा कारोबारी यासीन मछली का नाम इस नेटवर्क के केंद्र में लिया जा रहा है। बताया जाता है कि कोकता इलाके में स्थित उसके फार्म हाउस में करोड़ों रुपये के हिसाब-किताब का लेनदेन होता है। सूत्रों का दावा है कि यहां अवैध वित्तीय गतिविधियों के लिए उन्नत तकनीक और सुरक्षित स्थान का उपयोग किया जाता है, जिससे कानून की पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह फार्म हाउस क्षेत्र में लंबे समय से चर्चा का विषय रहा है, लेकिन किसी बड़ी कानूनी कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई है।

सारंग ने फैलाया नरेला में सट्टे का नेटवर्क

सूत्रों के अनुसार नरेला विधानसभा क्षेत्र में सट्टा कारोबार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है। करोंद, अशोका गार्डन, चांदबड, सुभाषनगर और ऐशबाग जैसे इलाकों में इसकी जड़ें गहरी बताई जाती हैं। (शेष पेज 5 पर)

सम्पादकीय

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रवैया और भारत के साथ बनते बिगड़ते रिश्ते

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने वैश्विक राजनैतिक संबंधों में पारंपरिक दोस्ताना रिश्तों की जगह व्यापार और दबाव-आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। भारत के साथ संबंधों में भी यही नीति लागू हुई। फरवरी 2025 में भारत और अमेरिका के बीच $500 अरब के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य की घोषणा के बावजूद ट्रंप ने भारत को "टैरिफ किंग" और "बड़ा दुर्व्यव्यहारकर्ता" करार दिया। अप्रैल 2025 में अमेरिका ने 'रिसिप्रोकल टैरिफ' लागू किया। 25% तक जिसे बाद में अगस्त में दुगना कर 50% कर दिया गया। यह कड़ा रुख व्यापार प्रतिबंधों और आर्थिक लाभों पर केंद्रित रहा, न कि दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग पर। भारत की रूस से तेल और रक्षा खरीद विशेष रूप से सस्ते तेल के लिए पर अमेरिका ट्रंप प्रशासन असहज था। जुलाई–अगस्त 2025 की कार्रवाई में, ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात को लेकर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जो कुल 50% तक हो गया। रूस की अर्थव्यवस्था को उस युद्ध के समर्थन से बाहर निकालना, जो यूक्रेन में हो रहा है। लेकिन सुपूर्दनीय परिणामित प्रभाव नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत के 40–45% तेल आयात रूस से ही हो रहे हैं।

भारत का "बहुपक्षीय विदेश नीति" और आत्मनिर्भरता पर जोर अमेरिका को हमेशा पसंद नहीं आया। विदेशी मामलों में मध्यस्थता, जैसे चीन-भारत या भारत–पाक संघर्ष में—भारत की स्पष्ट अस्वीकार्यता कारण रही। ट्रंप प्रशासन ने इसके बजाय भारत के रणनीतिक निर्णयों को घेरने का प्रयास किया आम रूप से पकड़ बनाया। अमेरिकी चुनाव एवं घरेलू राजनीतिक संदर्भ ट्रंप को भारत पर कड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। भारत से कड़े टैरिफ "टैरिफ किंग" का रूप देने का माध्यम यह नीति घरेलू चुनावी संदेश देना। जैसे-जैसे ट्रंप की नीतियाँ तंगी से भारत अमेरिका साझेदारी में विश्वासों पर धब्बा लगाने लगी। "लंबा दौर पहले से बना हुआ मजबूत साझेदारी" जिसे अब "स्लो-मोशन कैटास्ट्रोफ़" कहा जा रहा है। व्यापार और दबाव-आधारित दृष्टिकोण कलाकारिता, भावनात्मक बंधन के बजाय आर्थिक–रणनीतिक लाभ।भारत–रूस संबंधों पर असहमति विशेषातः तेल और रक्षा खरीद। भारत की विदेश नीति में रणनीतिक अखंडता अमेरिकी अपेक्षाओं से भिन्न। अमेरिकी घरेलू राजनीति और चुनावी रणनीति। भरोसे का क्षरण क्लासिक सहयोग की जगह अब चार्टेड बर्ताव का दबाव। भारत ने अभी भी अपनी रणनीतिक स्वतन्त्रता बरकरार रखी है, और आगामी विकल्पों जैसे आयात स्रोत विविधीकरण, घरेलू समर्थन या कानूनी राजनीतिक संतुलन का सहारा लेने की तैयारी में है। इस तनाव में भारत, चीन या रूस से अधिक डटे और जागरूक स्थिति अपनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है।

सियासी गहमागहमी

यासीन मछली की गिरफ्तारी से कई अफसर नेताओं के छूटे पसीने

यासीन मछली की गिरफ्तारी होते ही शहर के सियासी और अफसरशाही तालाब में लहरें उठ गईं। जैसे ही पुलिस ने जाल फेंका, उसमें सिर्फ मछली ही नहीं, बल्कि कई लोगों के सपनों और चैन की भी फड़फड़ाहट सुनाई देने लगी। ये वही यासीन मछली है, जिसके बारे में चर्चा थी कि वह सिर्फ पानी में नहीं, बल्कि सत्ता के गलियारों में भी आराम से तैरती थी। फर्क बस इतना था कि पानी में वह चुपचाप रहती, पर नेताओं और अफसरों के साथ आते ही उसकी बातें लहरों की तरह दूर-दूर तक फैल जातीं। गिरफ्तारी की खबर आते ही कई चेहरों पर चिंता की झील गहरी हो गई। कुछ नेता अचानक बीमार पड़ गए, मानो मछली नहीं पकड़ी गई हो, बल्कि उनका ब्लड प्रेशर पकड़ा गया हो। कुछ अफसरों ने पुराने कागज टटोलने शुरू कर दिए, ताकि अगर जांच की लहर उनकी ओर बढ़े तो पहले से बचाव की नाव तैयार रहे। चाय की दुकानों से लेकर व्हाट्सऐप ग्रुप तक, हर जगह चर्चा थी"भाई, मछली बड़ी है, जाल और बड़ा होगा।" कोई कह रहा था, "अभी तो पानी से निकली है, देखना बर्फ के टुकड़े पर रखकर कौन-कौन तस्वीर खिंचवाता है।" वहीं कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, "अब तो सीक्रेट फीडिंग का राज भी खुलेगा किसने किस दिन कितनी दाना-पानी दिया।" यासीन मछली अब हिरासत में है, पर डर और पसीने की बौछार बाहर है।

कमलनाथ की कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने का यह कदम कुछ नेताओं नहीं आया पसंद

कमलनाथ ने कांग्रेस को मजबूती देने के लिए एक नया कदम उठा दिया। अब, मजबूती किस तरह की है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ नेताओं को यह ऐसे लगा मानो पार्टी के खंभे सीधा करने के चक्कर में उनके आरामकुर्सी हिल गई हो। दरअसल, पार्टी को मजबूती देने का मतलब आम नेताओं के लिए होता है। बैठकों में चाय-पानी, बयानबाजी और चुनाव आने पर बैनर में फोटो। लेकिन यहां तो मामला अलग निकला। कमलनाथ ने सोचा, 'पार्टी की नींव पक्की करनी है,' और कुछ नेताओं ने तुरंत हिसाब लगाया' नींव पक्की हुई तो ऊपर की मंजिल में हमारी खिड़की बचेगी या नहीं?' कई अनुभवी चेहरों को यह कदम ऐसे लगा जैसे किसी ने उनके राजनीतिक दरवाजे पर ताला लगाने की तैयारी कर ली हो। अब कांग्रेस के गलियारों में यह चर्चा है कि मजबूती का यह इंजेक्शन पार्टी में जोश बढ़ाएगा या कुछ नेताओं का ब्लड प्रेशर। पर इतना तय है कमलनाथ के इस कदम ने कम से कम चुप बैठे नेताओं को बोलने का मौका तो दे ही दिया है, भले ही वह फुसफुसाहट में हो।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

विश्व आदिवासी दिवस पर सभी आदिवासी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं।

आपकी परंपराओं और जीवन मूल्यों ने भारत की पहचान को समृद्ध किया है।
आप भारत के पहले मालिक हैं और आपके अधिकार, अस्मिता और न्याय की लड़ाई में हम आपके साथ हैं।

-राहुल गांधी

कांग्रेस नेता @RahulGandhi

संस्कृत केवल भाषा नहीं, बल्कि भारत की ज्ञान परंपरा का स्रोत है।

आइए, हम सभी 'विश्व संस्कृत दिवस' पर इस महान भाषा की गरिमा, वैज्ञानिकता और सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान दें।-

कमलनाथ

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष

@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

भरोसेमंद और निष्ठावान राजनेता के रूप में नरेंद्र सिंह तोमर को मिली पहचान

समता पाठक/जगत प्रवाह

वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का जन्म 12 जून 1957 को प्रभासपुरा (पोरसा विकासखंड), मुरैना जिले के मोरार गाँव (ग्वालियर क्षेत्र), मध्यप्रदेश में हुआ। वे एक राजपूत परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तोमर संगठनात्मक कुशलता, रणनीतिक नेतृत्व और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। विशेषकर उन्होंने पंचायत राज, ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण जैसे क्षेत्रों में ठोस कार्य किए, जिनसे उनकी छवि एक भरोसेमंद और निष्ठावान राजनेता के रूप में बनी। उनकी राजनीति की शुरुआत छात्र संगठनों से हुई। वर्ष 1974-77 के दौरान वे भारतीय युवा संघ के वार्ड अध्यक्ष रहे। फिर क्रमशः 1977-78 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, 1980-84 में ग्वालियर जिले में BJYM के अध्यक्ष, 1984-85 में प्रदेश मंत्री तथा 1986-90 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने। उन्होंने 1991-96 तक BJYM के प्रदेश अध्यक्ष व फिर 1996-98 में प्रदेश प्रभारी के रूप में कार्य किया। वर्ष 1983-87 के दौरान वे ग्वालियर नगर निगम के पार्षद चुने गए। इसके बाद 1998 में पहली बार ग्वालियर से मध्यप्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए और 2003 तक इसी सीट पर निर्वाचित रहे। इस दौरान वे उमा भारती, बाबूलाल गौर तथा शिवराज सिंह चौहान सरकारों में विभिन्न विभागों- जैसे ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पशुपालन, जनसंपर्क (फिशरीज, पब्लिक रिलेशंस आदि) के मंत्री के रूप में कार्यरत रहे।

वर्ष 2006-10 के दौरान मध्यप्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे और उस समय पार्टी को विधानसभा चुनावों में सफलता दिलाने में उनकी महती भूमिका रही। वर्ष 2009 में राज्यसभा सदस्य चुने गए और इसके कुछ समय बाद लोकसभा चुनाव में मुरैना से सांसद बने। इसके बाद 2014 में ग्वालियर और 2019 में पुनः मुरैना से सांसद बने। श्रम एवं रोजगार, स्टील और खनन (2014–2016) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज (2016–2021), आवास एवं शहरी मामलों (2017) खनन (2017–2019), संसदीय कार्य (2018–2019) कृषि एवं किसान कल्याण (2019–2023), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (2020–2021)। दिसंबर 2023 में उन्हें मध्यप्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया। वर्तमान में वे विधानसभा स्पीकर और विधायक (दिमानी निर्वाचन क्षेत्र) हैं।

सत्ता, सट्टा, ड्रग्स और सवाल नरेला विधानसभा से जुड़े विवाद पर राजनीतिक हलचल

(पेज 3 का शेष)

कई स्थानीय दुकानों, ठेलों और आवासीय परिसरों में इस नेटवर्क के सक्रिय होने की चर्चा है। कई लोगों का कहना है कि इस कारोबार से जुड़े लोग न केवल खेल आयोजनों पर सट्टा लगवाते हैं बल्कि स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न घटनाओं और चुनाव परिणामों पर दांव लगाते हैं।

यासीन मछली के विश्वास सारंग से संबंध

मंत्री विश्वास सारंग और यासीन मछली के संबंध ताजे नहीं हैं। सारंग परिवार से यासीन के पुराने समय से हैं। जब कैलाश सारंग राजनीति में सक्रिय थे तबसे उनके संबंध हैं। जिसकी पुष्टि खुद विश्वास सारंग करते हैं। यासीन मछली का नाम स्थानीय स्तर पर कोई नया नहीं है। सूत्रों के मुताबिक यह नाम शहर के कई थानों की रिपोर्ट में बार-बार सामने आता रहा है। हालांकि कोई बड़ी सार्वजनिक कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई है। कहा जाता है कि उसका कोकता स्थित फार्म हाउस, सट्टे और अन्य संदिग्ध लेन-देन का मुख्य अड्डा है। वहीं कुछ स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार इस फार्म हाउस में न केवल सट्टा, बल्कि हवाला, कैश स्टोरेज और अन्य संदिग्ध गतिविधियों के संचालन की भी आशंका है। पड़ोसी ग्रामीणों का कहना है कि फार्म हाउस पर गतिविधियां अक्सर रात के समय होती हैं और वहां बाहरी नंबर की महंगी गाड़ियों की आवाजाही आम है।

मछली पर राजनीतिक संरक्षण के आरोप

सूत्रों का दावा है कि इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और इसमें मंत्री विश्वास सारंग का नाम लिया जा रहा है। आरोप है कि सारंग के संरक्षण में नरेला क्षेत्र में यह कारोबार वर्षों से चल रहा है और अब प्रदेश का सबसे बड़ा सट्टा हब बन चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन दोनों के लिए गंभीर चुनौती हो सकती है। मछली पर धर्मांतरण के भी आरोप लगे हैं। वह अपने रसूख और पैसों के दम पर लोगों को धर्मांतरण के लिए दबाव डालता था।

सारंग पर लगे कई घोटालों के आरोप

विश्वास सारंग पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे और वर्तमान में खेल एवं सहकारिता विभाग संभाल रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इन दोनों मंत्रालयों में रहते हुए करोड़ों रुपये के घोटाले हुए। विपक्षी नेताओं ने कई बार विधानसभा और मीडिया में इन मुद्दों को उठाया है। हालांकि, इन आरोपों की अब तक किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं हुई है।

भाजपा के भीतर सारंग को लेकर चर्चा

भाजपा के नए प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल संगठन की छवि सुधारने के लिए सक्रिय हैं और इसीलिए वह इस मुद्दे पर सारंग से बातचीत कर सकते हैं। माना जा रहा है कि संगठन ऐसे आरोपों को गंभीरता से ले रहा है, खासकर तब जब विपक्ष लगातार इस पर हमला कर रहा हो। भाजपा संगठन के कुछ आंतरिक सूत्रों का यह भी दावा है कि खंडेलवाल इन चर्चाओं के मद्देनजर सारंग से जवाब तलब कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो यह पार्टी स्तर पर एक बड़ा कदम माना जाएगा।

विपक्ष ने की सारंग पर लगे आरोपों के जांच की मांग

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने कहा कि यदि भाजपा वास्तव में भ्रष्टाचार और अवैध कारोबार के खिलाफ है तो उसे अपने मंत्री पर लगे आरोपों की जांच तुरंत करानी चाहिए। क्षेत्र के निवासियों के बीच इस मामले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। कुछ लोग मानते हैं कि सट्टा कारोबार ने कई युवाओं को आर्थिक और सामाजिक संकट में डाल दिया है, जबकि कुछ का कहना है कि इस कारोबार से कई लोगों की रोजी-रोटी भी चल रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि पार्टी स्तर पर सारंग को लेकर कोई सख्त निर्णय लिया जाता है, तो यह संगठन के भीतर अनुशासन और पारदर्शिता का संदेश देगा। वहीं, यदि मामला लंबा खिंचता है तो विपक्ष को हमले का और अधिक मौका मिलेगा।

नरेला की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति

नरेला विधानसभा क्षेत्र राजधानी भोपाल के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में स्थित है। यहां शहरी और ग्रामीण दोनों वर्गों की मिश्रित आबादी है। इस क्षेत्र में विश्वास सारंग का लंबे समय से दबदबा रहा है और वे यहां से बार-बार चुने गए हैं। ऐसे में किसी बड़े अवैध नेटवर्क का उजागर होना राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो सकता है।

उत्तराखंड में जल-प्रलय

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

भगवान भोले नाथ का गुस्सा, प्रतीक रूप में मौत के तांडव नृत्य में फूटता है। देवभूमि उत्तराखंड में शिव के इस तांडव नृत्य का सिलसिला केदारनाथ में 2013 में आई प्राकृतिक आपदा के बाद अभी भी जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की खीर गंगा नदी और धराली में बादल फटने और हर्शिल के तेल गाड़ नाले में बाढ़ आने से बड़ी तबाही हुई है। इन प्राकृतिक आपदाओं को हमें इसी गुस्से के प्रतीक रूप में देखने की जरूरत है। धराली में तो 50 से ज्यादा घर, 30 होटल और 30 होमस्टे मलबे में बदल गए। जो खीर नदी 10 मी. चौड़ी थी, वह जल प्रवाह से 39 मी. चौड़ी हो गई। अतएव जो भी सामने पड़ा उसे लीलती चली गई। प्रशासन चार लोगों की मौत और 100 से अधिक लोगों के लापता होना बता रहा है। लेकिन हिमालय के बीचोंबीच बसा खूबसूरत धराली गांव में सैलाब नीचे उतरते हुए दिखा, उससे लगता है, मौतें कहीं अधिक हुई हैं। प्रलय इतनी तीव्रता से आया की उसकी कान के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जना सुनने के बाद लोगों को बचने का समय ही नहीं मिल पाया। अब धराली मलबे में दफन है।

इस भूक्षेत्र के गर्भ में समाई प्राकृतिक संपदा के दोहन से उत्तराखंड विकास की अग्रिम पांत में आ खड़ा हुआ था, वह विकास भीतर से कितना खोखला था, यह इस क्षेत्र में निरंतर आ रही इस आपदाओं से पता चलता है। बरिश, बाढ़, भूस्खलन, बर्फ की चट्टानों का टूटना और बदलों का फटना, अनायास या संयोग नहीं है,बल्कि विकास के बहाने पर्यावरण विनाश की जो पृष्ठभूमि रची गई, उसका परिणाम है। तबाही के इस कहर से यह भी साफ हो गया है कि आजादी के 78 साल बाद भी हमारा न तो प्राकृतिक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा से निपटने में सक्षम है और न ही मौसम विभाग आपदा की सटीक भविश्यवाणी करने में समर्थ हो पाया है। यह विभाग केरल और बंगाल की खाड़ी के मौसम का अनुमान लगाने का दावा तो करता है, किंतु भारत के सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र हिमालय में बादल फटने की भी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है। जबकि धराली क्षेत्र में एक साथ दो जगह बादल फटे और कुछ मिनटों में हुई तेज बारिश ने श्रीखंड पर्वत से निकली खीरगंगा नदी को प्रलय में बदलकर 90 प्रतिशत गांव को हिमालय के गर्भ में समा दिया।

बादल फटना अनायास जरूर है, लेकिन ये करीब 10 किमी व्यास की परिधि में फटने के बाद अतिवृष्टि का कारण बनते हैं। 10 सेंटीमीटर या उससे अधिक बारिश को बादल फटने की घटना के रूप में पारिभाषित किया जाता है। बादल फटने की घटना के दौरान किसी एक स्थान पर एक घंटे के भीतर, उस क्षेत्र में होने वाली औसत, वार्षिक वर्षा की 10 प्रतिशत से अधिक बारिश हो जाती है। मौसम विभाग वर्षा का पूर्वानुमान कई दिन या माह पहले लगा लेते हैं। लेकिन मौसम विज्ञानी बादल फटने जैसी बारिश का अनुमान नहीं लगा पाते। इस कारण बादल फटने की घटनाओं की भविष्यवाणी भी नहीं करते हैं।

समृद्धि, उन्नति और वैज्ञानिक उपलब्धियों का चरम छू लेने के बावजूद प्रकृति का प्रकोप धरा के किस हिस्से के गर्भ से फूट पड़ेगा या आसमान से टूट पड़ेगा, यह जानने में हम बौने ही हैं। भूकंप की तो भनक भी नहीं लगती। जाहिर है, इसे रोकने का एक ही उपाय है कि विकास की जल्दबाजी में पर्यावरण की अनदेखी न करें। लेकिन विडंबना है कि घरेलू विकास दर को बढ़ावा देने के मद्देनजर अधोसंरचना विकास के बहाने देशी-विदेशी पूंजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों राज्य सरकारें अब अनदेखा करने लगी हैं। इससे साबित होता है कि अंततः हमारी वर्तमान अर्थव्यस्था का मजबूत आधार अटूट प्राकृतिक संपदा और खेती ही हैं। लेकिन उत्तराखंड हो या प्राकृतिक संपदा से भरपूर अन्य प्रदेश उद्योगपतियों की लाँबी जीडीपी और विकास दर के नाम पर पर्यावरण सबंधी कठोर नीतियों को लचीला बनाकर अपने हित साधने में लगी हैं। विकास का लॉलीपॉप प्रकृति से खिलवाड़ का करण बना हुआ है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में आई इन तबाहियों का आकलन इसी परिप्रेक्ष्य में करने की जरूरत है।

उत्तराखंड, उप्र से विभाजित होकर 9 नवंबर 2000 को अस्तिव में आया था। 13 जिलों में बंटे इस छोटे राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 1 करोड़ 11 लाख है। 80 फीसदी साक्षरता वाला यह प्रांत 53,566 वर्ग किलोमीटर में फैला है। उत्तराखंड में भागीरथी, अलकनंदा, गंगा और यमुना जैसी बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली नादियों का उद्गम स्थल है। इन नादियों के उद्गम स्थलों और किनारों पर पुराणों में दर्ज अनेक धार्मिक व सास्कृतिक स्थल हैं। इसलिए इसे धर्म-ग्रंथों में देवभूमि कहा गया है। यहां के वनाच्छादित पहाड़ अनूठी जैव विविधता के पर्याय हैं। तय है, उत्तराखंड प्राकृतिक संपदाओं का खजाना है। इसी बेशकीमती भंडार को सत्ताधारियों और उद्योगपतियों की नजर लग गई है, जिसकी वजह से प्रलय जैसे प्रकोप बार-बार इस देवभूमि में बर्बादी की आपदा वर्शा रहे हैं। उत्तराखंड की तबाही की इबारत टिहरी में गंगा नदी पर बने बड़े बांध के निर्माण के साथ ही लिख दी गई थी। नतीजतन बड़ी संख्या में लोगों का पुश्तैनी ग्राम-कस्बों से विस्थापन तो हुआ ही, लाखों हेक्टेयर जंगल भी तबाह हो गए। बांध के निर्माण में विस्फोटकों के इस्तेमाल ने धरती के अंदरूनी पारिस्थिकी तंत्र के ताने-बाने को खंडित कर दिया। विद्युत परियोजनाओं और सड़कों का जाल बिछाने के लिए भी धमाकों का अनवरत सिलसिला जारी रहा। अब यही काम रेल पथ के लिए सुरंगे बनाने में सामने आ रहा है। विस्फोटों से फैले मलबे को भी नदियों और हिमालयी झीलों में ढहा दिया जाता है। नतीजतन नदियों का तल मलबे से भर गए हैं। दुष्परिणाम स्वरूप इनकी जलग्रहण क्षमता नष्ट हुई और जल प्रवाह बाधित हुआ। अतएव जब भी तेज बारिश आती है तो तुरंत बाढ़ में बदलकर विनाशलीला में तब्दील हो जाती है। बादल फटने के तो केदारनाथ और अब धराली जैसे परिणाम निकलते है। उत्तरकाशी, जोशीमठ में तो निरंतर बाढ़ और भू-स्खलन देखने में आ रहे हैं, इस क्षेत्र के सैंकड़ों मकानों में भूमि घसंकने से बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं। भू-स्खलन के अलावा इन दरारों की वजह कालिंदी और असिगंगा नदियों पर निर्माणाधीन जलविद्युत और रेल परियोजनाएं भी रही हैं।

उत्तराखंड जब स्वंतत्र राज्य नहीं बना था, तब इस देवभूमि क्षेत्र में पेड़ काटने पर प्रतिबंध था। नदियों के तटों पर होटल नहीं बनाए जा सकते थे। यहां तक कि निजी आवास बनाने पर भी रोक थी। लेकिन उत्तर प्रदेश से अलग होने के साथ ही, केंद्र से बेहिसाब धनराशि मिलना शुरू हो गई। इसे ठिकाने लगाने के नजरिए स्वयंभू ठेकेदार आगे आ गए। उन्होंने नेताओं और नौकरशाहों का एक मजबूत गठजोड़ गढ़ लिया और नए राज्य के रहनुमाओं ने देवभूमि के प्राकृतिक संसाधनों के लूट की खुली छूट दे दी। दवा (फार्मा) कंपनियां औषधीय पेड़-पौधों और जड़ी-बूटियों के दोहन में लग गई हैं। भागारथी, खीरगंगा और अलकनंदा के तटो पर बहुमंजिला होटल और आवासीय इमारतों की कतार लग गई। पिछले 25 साल में राज्य सरकार का विकास के नाम पर प्रकृति के दोहन के अलावा कोई उल्लेखनीय काम नहीं है। जबकि इस राज्य का निर्माण का मुख्य लक्ष्य था कि पहाड़ से पलायन रुके। रोजगार की तलाश में युवाओं को महानगरों की और ताकना न पड़े। लेकिल 2011 में हुई जनगणना के जो आंकड़े सामने आए हैं, उनके अनुसार पौढ़ी-गढ़वाल और अल्मोड़ा जिलों की तो आबादी ही घट गई है। तय है, क्षेत्र में पलायन और पिछड़ापन बढ़ा है। विकास की पहुंच धार्मिक स्थलों पर ही सीमित रही है,क्योंकि इस विकास का मकसद महज श्रद्धालुओं की आस्था का आर्थिक दोहन रहा था। यही वजह रही कि उत्तराखंड के 5 हजार गांवों तक पहुंचने के लिए सड़कें नहीं हैं। खेती आज भी वर्शा पर निर्भर है। उत्पादन बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन सुविधाएं नदारद हैं। तिस पर भी छोटी बड़ी प्राकृतिक आपदाएं कहर ढाती रहती हैं। इस प्रकोप ने तो तथाकथित आधुनिक विकास को मिट्टी में मिलाकर जल के प्रवाह में बहा दिया। ऐसी आपदाओं की असली चुनौती इनके गुजर जाने के बाद खड़ी होती है, जो अब जिस भयावह रूप में देखने में आ रही है, उसे संवेदनशील आंखों से देखा जाना भी मुश्किल है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआतः मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

-शशि पांडे

जगत प्रवाह. रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णदेव साय पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ शासन, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर और मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के मध्य हुए त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर के साक्षी बने। इस समझौते के अंतर्गत स्थापित होने वाले उद्यमिता केंद्र का निर्माण वर्ष 2025-26 में प्रारंभ होगा तथा इसे वर्ष 2027-28 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर कहा कि आज हस्ताक्षरित एमओयू से "छत्तीसगढ़ अंजोर विजन" को साकार करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी। इस साझेदारी से प्रदेश में गांव-गांव तक शिक्षा, कौशल विकास और नवाचार की क्रांति पहुंचेगी, जो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस त्रिपक्षीय समझौते के तहत "श्रीमती मिथिलेश अग्रवाल नवाचार एवं उद्यमिता उत्कृष्टता केंद्र" की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को शोध, प्रयोग और उद्यमिता के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह उत्कृष्टता केंद्र केवल आईआईएम या एनआईटी के विद्यार्थियों तक सीमित न रहे, बल्कि गांव-गांव के युवाओं को भी लाभान्वित करे। मुख्यमंत्री ने उद्योग जगत से भी इस शिक्षा और कौशल विकास के आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री साय ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ अब कोर सेक्टर के साथ-साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फार्मा, डिफेंस, एयरोस्पेस और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर हो रहा है। बीते 20 महीनों में किए गए साढ़े तीन सौ से अधिक सुधारों के परिणामस्वरूप राज्य में निवेश का अनुकूल वातावरण निर्मित हुआ है और केवल आठ माह में 6.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि हम सभी यह संकल्प लें कि छत्तीसगढ़ को संसाधन-आधारित नहीं, बल्कि नवाचार-आधारित अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने वाला राज्य बनाएंगे-जहाँ युवा बदलाव के वाहक बनें और उद्यमिता से समाज को दिशा दें। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारीक, उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के सचिव एस. भारतीदासन, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय दयाराम के, एनआईटी रायपुर के चेयरमैन डॉ. सुरेश हावरे, आईआईएम रायपुर के चेयरमैन पुनीत डालमिया, एनआईटी के निदेशक श्री एन. वी. प्रसन्ना राव, आईआईएम रायपुर के प्रभारी निदेशक डॉ. संजीव पाराशर, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षाविद एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में बढ़ी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कराने की तिथि

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह. रायपुर। किसानों की सुविधा के देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बीमा कराने की तिथि बढ़ा दी गई है। अऋणी किसान अब 14 अगस्त और ऋणी किसान 31 अगस्त तक 2025 तक बीमा करा सकेंगे। राजनांदगांव जिले के उप संचालक कृषि, टीकम सिंह ठाकुर ने किसानों से अपनी फसलों का बीमा कराने लिए निकटतम लोक सेवा केंद्र, बैंक या समिति में संपर्क कर शीघ्र बीमा कराने की अपील की है। राजनांदगांव के उपसंचालक कृषि ने बताया कि जिले में वर्ष 2025 में अब तक 1,065.81 हेक्टेयर रकबे का फसल बीमा कराया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जिले में वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 1 लाख 17 हजार 866 किसानों ने बीमा कराया है। इनमें 1 लाख 9 हजार 178 ऋणी किसान और 8 हजार 688 अऋणी किसान शामिल थे। इस अवधि में कुल 1 लाख 43 हजार 465.56 हेक्टेयर रकबे का बीमा हुआ। फसल कटाई उपरांत प्राप्त उपज आंकड़ों के आधार पर 2,733 किसानों को कुल 6 करोड़ 21 लाख 19 हजार 101 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की गई।

इसी प्रकार रबी वर्ष 2024-25 में कुल 31 हजार 634 किसानों ने बीमा कराया, जिनमें 19 हजार 473 ऋणी किसान और 12 हजार 161 अऋणी किसान शामिल रहे। इस दौरान 39 हजार 431.58 हेक्टेयर रकबे का बीमा हुआ। फसल कटाई उपरांत आंकड़ों के अनुसार 20 हजार 380 किसानों के लिए 33 करोड़ 23 लाख 21 हजार 247 रुपये का दावा गणना पूर्ण कर लिया गया है, जिसका भुगतान डीजी क्लेम पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। गौरतलब है कि पीएम फसल बीमा माध्यम से किसानों को किफायती दर पर फसल बीमा उपलब्ध कराकर कृषि उत्पादन को सुरक्षित और सशक्त बनाया जा रहा है। यह योजना बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक के चरण में, क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर, सभी गैर-रोकथाम योग्य प्राकृतिक जोखिम से किसानों की फसलों के लिए व्यापक सुरक्षा कवच प्रदान करती है।

धराली त्रासदी प्राकृतिक आपदा नहीं चेतावनी है

पर्यावरण की फिक्र

डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

उत्तराखंड के धराली, गंगोत्री यात्रा की एक पड़ाव, की एक घटना ने ऐसी तबाही मचाई है कि इलाके का भूगोल ही बदल चुका है। इस घटना से पहले जहां होटल, घर, दुकानें, जन-जीवन था। वहां अब चारों तरह दूर-दूर तक केवल मलबा नजर आ रहा है। धराली त्रासदी भयानक क्यों हुई इस पर चिंतन करना जरूरी है।धराली त्रासदी न होती अगर खीरगंगा नदी के रास्ते पर भारी रिहायश न बसी होती। धराली की अधिकांश रिहायशी यहां लैंडस्लाइड के पुराने मलबे पर बसी हुई है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक खीरगंगा पहले भी इस तरह विकराल होती रही है और अपने साथ भारी मलबा लेकर आती रही है। 1835 में ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें कुछ घर दब गए और क़रीब बना कल्प केदार मंदिर भी मिट्टी में दब गया। बाद में इस मंदिर को खोद कर बाहर निकाला गया लेकिन उसके आसपास का इलाका आज भी उस लैंडस्लाइड में दबा हुआ है। ये ऐतिहासिक तथ्य बताता है कि धराली में खीरगंगा नदी के मुहाने पर बसना एक बहुत बड़ी ग़लती रही। अफ़सोस ये है कि ऐसी ग़लती हिमालय में कई रिहायशी इलाके में रहे हैं और नदियों के बिलकुल आसपास बने हुए हैं जो कभी भी ख़तरनाक हो सकता है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का आदेश कहता है कि नदियों के दोनों किनारों पर सौ मीटर की दूरी तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे आदेशों का धड़ल्ले से उल्लंघन हो रहा है जो हर साल भारी पड़ रहा है।हिमालय में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गहरे और व्यापक हैं। पिछले 50 वर्षों में हिमालय का तापमान लगभग 1.8C बढ़ा है, जो वैश्विक औसत से लगभग दोगुना तेजी है, जिससे हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इससे हिमनदों की झीलों का अचानक टूटना (ग्लेशियल झील विस्फोट बाढ़- GLOFs) का खतरा बढ़ गया है, जो क्षेत्र में आपदाओं को जन्म देता है। उदाहरण के तौर पर, 2023 में सिक्किम में ऐसी घटना हुई थी। जलवायु परिवर्तन से हिमालय में अनियमित और तीव्र मौसम पैटर्न बन रहे हैं, जिनमें हिंसक मानसूनी तूफान और अचानक भारी बारिश शामिल हैं। यह आपदाएं न केवल जन-धन को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी प्रभावित करती हैं। स्थिर ढलानों पर होती असामयिक निर्माण गतिविधियां और अव्यवस्थित पर्यटन पर्यावरणीय असंतुलन को और बढ़ा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हिमालयी क्षेत्र में "प्रतिबद्ध तापन" (committed warming) की वजह से पहले से अपरिवर्तनीय जलवायु परिणाम दिखाई दे रहे हैं, जिनसे आपदा जोखिम बढ़ता जा रहा है। अध्ययन बताते हैं कि हिमालय सहित हाई माउंटेन एशिया में पिछले 2000 से बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जिसमें तेज बारिश, हिमनद टूटना, भूस्खलन के कारण बनी झीलों के टूटने जैसे कारण प्रमुख हैं। वैश्विक तापमान में हर 1C वृद्धि से ऊंचे क्षेत्रों में औसत बारिश लगभग 15% बढ़ सकती है, जो बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है।

सामाजिक स्तर पर इससे मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याएं भी उभर रही हैं, खासकर हाशिये पर रहने वाले समुदायों में। अध्ययन बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय में मृदा अपरदन बढ़ रहा है, जैव विविधता घट रही है, और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र अस्थिर हो रहा है। कृषि, पशुपालन, वन उत्पादों और पर्यटन, जो हिमालयी लोगों की आजीविका के मुख्य स्रोत हैं, पर नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। इसलिए हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में तापमान वृद्धि, ग्लेशियर पिघलाव, आपदा की बढ़ती घटनाएं जैसे बाढ़, भूस्खलन, ग्लेशियल झील विस्फोट, बादल का फटना, पर्यावरणीय क्षरण, और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियां शामिल हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए स्थायी विकास, पर्यावरण संरक्षण, प्रभावी आपदा प्रबंधन, और जलवायु अनुकूल आधारभूत संरचना जरूरी है उत्तराखंड की धराली की घटना हो या फिर केदारनाथ, की भारत हो या अमरीका और यूरोप, पर्यावरणविदों और वैज्ञानिकों ने हमेशा चेताया है कि अगर क़ुदरत के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोका नहीं गया तो भारी नुक़सान उठाना पड़ सकता है।

विश्व आदिवासी दिवस विशेष

संस्कृति, संघर्ष और समाधान की आदिवासी गाथा

"जब आप किसी आदिवासी समूह को देखते हैं, तो आप सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी प्रकृति की आत्मा को साक्षात देखते हैं। उन्हें समझने के लिए आँखें नहीं, हृदय की दृष्टि चाहिए।" आज जब पूरा विश्व आदिवासी दिवस मना रहा है, तो मेरा मन 40 साल पीछे, उस दौर में लौट जाता है, जब मैंने एक युवा सब-इंस्पेक्टर के रूप में अलीराजपुर की धरती पर पहला कदम रखा था। तब अलीराजपुर, झाबुआ जिले का एक हिस्सा था और यह क्षेत्र एशिया के सबसे अधिक अपराध प्रभावित क्षेत्रों में गिना जाता था। वर्दी की अपनी चुनौतियाँ थीं, लेकिन उस दुर्गम इलाके ने मुझे जो सिखाया, वह किसी किताब या ट्रेनिंग में मिलना असंभव था।

आज की बात

प्रवीण कक्कड़
स्वतंत्र लेखक

वो दौर : जब जंगल का न्याय कानून पर भारी था

मैंने अपनी आँखों से देखा कि अपराध की जड़ें समाज की गहराइयों में कैसे पनपती हैं। वहां अपराध महज़ एक घटना नहीं, बल्कि अभाव, अशिक्षा और अवसरों की कमी से उपजा एक परिणाम था।

शिक्षा और स्वास्थ्य? मीलों तक कोई स्कूल या अस्पताल नहीं था। बीमारी का मतलब या तो स्थानीय जड़ी-बूटियों पर निर्भरता थी या फिर नियति के भरोसे रहना।

कानून का डर? लोगों के लिए जंगल का न्याय और गाँव के पंच का फैसला ही अंतिम सत्य था। थाने और अदालतें उनकी दुनिया से बहुत दूर थीं। जहां थाने का दरवाजा भी उतना ही दूर था, जितना शहर का सपना।

महिलाओं का संघर्ष: वे घर, खेत और परिवार की धुरी थीं, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह निर्भर और असुरक्षित।

लेकिन इस कठोर कैनवास पर मैंने संस्कृति के सबसे जीवंत रंग भी देखे। मैंने आदिवासियों के हृदय की सरलता, प्रकृति के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा और उनकी कला की गहराई को महसूस किया। होली से पहले जब भगोरिया का मेला सजता था, तो हवा में घुले मांदल के संगीत और युवाओं के उल्लास को देखकर लगता था मानो जीवन का उत्सव इससे बड़ा नहीं हो सकता। मैंने देखा कि वे पेड़ों को जीवित आत्मा, नदियों को माँ और पहाड़ों को देवता क्यों मानते हैं। उनकी जीवनशैली पिछड़ी नहीं, बल्कि आज की दुनिया के लिए 'सस्टेनेबल लिविंग' का सबसे बड़ा उदाहरण थी।

सफर बदला, नज़रिया बदला : वर्दी से लेकर नीति-निर्माण तक

समय के साथ मेरी भूमिका बदली। पुलिस अधिकारी के रूप में मैंने ज़मीन पर समस्याओं को समझा, तो बाद में केंद्रीय मंत्री और फिर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (OSD) के रूप में मुझे उन समस्याओं के समाधान के लिए नीतियां बनते और लागू होते देखने का अवसर मिला। यह एक अद्भुत अनुभव था। दिल्ली और भोपाल के दफ्तरों में जब आदिवासियों के विकास की फाइलें चलती थीं, तो मेरे सामने झाबुआ-अलीराजपुर के वो चेहरे घूम जाते थे। मैं जानता था कि एक सड़क का बनना सिर्फ आवागमन नहीं, बल्कि किसी बीमार बच्चे के लिए अस्पताल तक पहुँचने की उम्मीद है। एक स्कूल का खुलना सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि पीढ़ियों की गरीबी से मुक्ति का दरवाजा है।

पिछले 40 वर्षों में मैंने अपनी आँखों के सामने समाज को बदलते देखा है

कल: जहाँ स्कूल नहीं थे, आज वहाँ आवासीय विद्यालय हैं, जहाँ आदिवासी बच्चे पढ़-लिखकर आगे बढ़ रहे हैं।

कल: जो महिलाएँ केवल घर तक सीमित थीं, आज वे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनकर परिवार चला रही हैं।

कल: जो युवा दिशाहीन होकर अपराध की राह पकड़ते थे, आज उन्हीं में से कोई शिक्षक बन रहा है, कोई सेना में भर्ती हो रहा है तो कोई पुलिस अधिकारी बनकर समाज की सेवा कर रहा है। यह बदलाव सरकारों और समाज के सम्मिलित प्रयासों का ही नतीजा है। प्रयास हुए हैं, और उनके परिणाम भी दिख रहे हैं, लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि अभी मंजिल दूर है।

चुनौतियाँ आज भी हैं : अब हमें क्या करना है?

आज भी जब मैं उन क्षेत्रों में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि भौगोलिक कठिनाइयाँ, कुछ युवाओं में नशे की बढ़ती लत और बेहतर अवसरों के लिए होने वाला पलायन बड़ी चुनौतियाँ हैं। कभी-कभी लगता है कि विकास की कुछ योजनाएँ उदासीनता और अन्य कारणों से उन तक नहीं पहुँच पातीं, जिनके लिए वे बनी हैं। सबसे बड़ा खतरा उनकी संस्कृति के क्षरण का है, जो बाहरी चमक-दमक में अपनी पहचान खो रही है। यहाँ किसी को दोष देने का समय नहीं है। अब हमें एक साझा जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा।

समाज के रूप में: हमें आदिवासी समाज को 'पिछड़ा' या 'गरीब' समझकर सहानुभूति दिखाने की बजाय, उनके ज्ञान और हुनर का सम्मान करना होगा। उनकी कला, उनके हस्तशिल्प को बाजार देकर हम उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

सरकार के स्तर पर: योजनाओं को फाइलों से निकालकर ज़मीन पर प्रभावी ढंग से लागू करना होगा। हमें सुनिश्चित करना होगा कि जल, जंगल और ज़मीन पर उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो। युवाओं के लिए पारंपरिक कलाओं के साथ-साथ आधुनिक कौशल विकास और खेल-कूद के बेहतरीन अवसर बनाने होंगे।

यह उत्सव नहीं, एक संकल्प है

विश्व आदिवासी दिवस मेरे लिए केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि मेरे 4 दशक के अनुभवों का निचोड़ है। यह एक संकल्प लेने का दिन है कि हम आदिवासी समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। उनकी संस्कृति बचे भी, बढ़े भी और आने वाली पीढ़ियों को दिशा भी दे। क्योंकि सच तो यह है कि आदिवासी समाज को सशक्त करना, केवल एक समुदाय का विकास नहीं है, यह भारत की आत्मा को सींचना है। यह दिन सिर्फ आदिवासी समाज के लिए नहीं, हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रकृति, परंपरा और प्रगति के बीच संतुलन चाहता है। हमने एक अच्छी शुरुआत की है, पर अभी इस यज्ञ में बहुत कुछ करना बाकी है। आइए, हम सब मिलकर इस यज्ञ को पूरा करें।

छत्तीसगढ़ सरकार ने विकसित भारत निर्माण के लिए राज्य का संकल्प 'अंजोर विजन@2047', प्रधानमंत्री को किया रजत जयंती समारोह के लिए आमंत्रित

(पेज 1 का शेष)

शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर

विजन दस्तावेज में शिक्षा को सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मूल आधार माना गया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ का साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो और उच्च शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्मार्ट स्कूलों का निर्माण, डिजिटल शिक्षा और ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण, आदिवासी और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष शिक्षा मिशन का संचालन।

स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार

स्वास्थ्य क्षेत्र में 'अंजोर विजन' का लक्ष्य सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार, टेलीमेडिसिन सेवाओं को सुदृढ़ करना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी लाना, पोषण योजनाओं के माध्यम से कुपोषण समाप्त करना।

कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्तिकरण

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की केंद्रीय भूमिका को ध्यान में रखते हुए विजन में किसानों की आय दोगुनी करने के स्पष्ट लक्ष्य तय किए गए हैं। आधुनिक कृषि, तकनीकों का प्रसार, सिंचाई क्षमता में वृद्धि, फसल विविधीकरण और मूल्य संवर्धन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना। उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे में निवेश सरकार का मानना है कि रोजगार के अवसर बढ़ाने और आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उद्योग और नवाचार को बढ़ावा देना आवश्यक है।

स्टार्टअप इकोसिस्टम का विकास

खनिज आधारित उद्योगों के साथ-साथ हरित उद्योगों को प्रोत्साहन, परिवहन, ऊर्जा और डिजिटल कनेक्टिविटी में व्यापक सुधार, लॉजिस्टिक हब और औद्योगिक कॉरिडोर की स्थापना।

पर्यावरण एवं सतत विकास पर विशेष ध्यान

अंजोर विजन में जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रमुख प्राथमिकता दी गई है। वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण कार्यक्रम, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का विस्तार, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कठोर मानक, जल संरक्षण और प्रबंधन में जनसहभागिता।

प्रधानमंत्री को दिया रजत जयंती समारोह का आमंत्रण

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य के रजत जयंती समारोह में शामिल होने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि यह अवसर न केवल छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की विकास यात्रा का जश्न होगा, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का भी है। साय ने बताया कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति से राज्य के लोगों को नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी, साथ ही अंजोर विजन@2047 की दिशा में तेजी से काम करने का उत्साह बढ़ेगा।

रजत जयंती वर्ष गौरव और संकल्प का अवसर

साल 2000 में गठित हुआ छत्तीसगढ़ अब 25 वर्ष का हो रहा है। इस अवधि में राज्य ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली उत्पादन, खनिज संपदा और कृषि में उल्लेखनीय प्रगति की है। हालांकि, मुख्यमंत्री साय मानते हैं कि अभी भी राज्य के कई क्षेत्रों में विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। रजत जयंती समारोह के तहत राज्यभर में सांस्कृतिक कार्यक्रम, विकास प्रदर्शनी और जनसंवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन आयोजनों में अतीत की उपलब्धियों को रेखांकित करने के साथ भविष्य के लक्ष्यों की स्पष्ट रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी। अंजोर विजन@2047 केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लिए आने वाले 20-25 वर्षों का विकास पथ है। यह योजना राज्य को विकसित भारत के विजन से जोड़ते हुए उसे आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सभी मोर्चों पर मजबूत करने का खाका पेश करती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार का मानना है कि यदि यह विजन जनसहभागिता और केंद्र-राज्य के सामंजस्य से लागू होता है, तो 2047 में छत्तीसगढ़ न केवल विकसित भारत का हिस्सा होगा, बल्कि अपने आप में एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित होगा।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)